tutkfr; {k=k esa
dU;k f'k{kk dh leL;k,a

Problems of Girls Education in Tribal Areas

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

tutkfr; {k=k esa dU;k f'k{kk dh leL;k,a

Problems of Girls Education in Tribal Areas

y[kd

Mk- ,y- ,l- xtiky

(M.A.,Ph.D.,
JRF NET)

Associate Professor
School of Studies in Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur, Chhattisgarh (INDIA)

lg&y[kd

Mk- deyukjk;.k xtiky

Associate Professor
Department of Education
Pragati College, Raipur

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

दिल्ली (भारत)

नमूना • SAMPLE

}kjk izdkf'kr

AKHAND

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

tutkfr; {k=k esa dU;k f'k{kk dh leL;k,a
Problem's of Girls Education in Tribal Areas

संस्करण : 2019
© लेखक
ISBN: 978-93-88998-12-3

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

Hkkjr esa izdkf'kr

झपसू यादव द्वारा 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा वी.एम. ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE

izkDdFku

प्रस्तुत पुस्तक जनजातिय क्षेत्रों में कन्या शिक्षा पर आधारित है। पुस्तक में देश के सर्वाधिक संवेदनशील और अंर्तराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी संस्कृति के लिए जाने पहचाने जाने वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी विचारधारा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में जनजाति परिदृश्य में शिक्षा की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का शोधपरक ढ़ंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के साथ सुझाव भी प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से हिंसा से प्रभावित जनजाति क्षेत्रों में न केवल कन्या शिक्षा वरन सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। पुस्तक विषय के ज्ञान को बढ़ाने में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगी क्योंकि यह अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित है।

पुस्तक प्रकाशन के अवसर में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन संचालक के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनके आर्थिक सहयोग से शोध परियोजना पूर्ण हो सका और वह पुस्तक का आकार ले रहा है।

मैं दंतेवाड़ा जिले के सहायक आयुक्त डॉ. आनंद सिंह जी समाजशास्त्र अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा जी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने पिता श्री कुमारचंद गजपाल (सेवानिवृत्त शिक्षक), माताजी श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल के स्नेह और आर्शीवचन के प्रति अंर्तमन से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

,y- ,l- xtiky
deyukjk;.k xtiky

SAMPLE

नमूना • SAMPLE

fo"k; & lph

	प्राक्कथन	*v*
1.	प्रस्तावना	1
2.	भारतीय बच्चे : एक विवरण	13
3.	अध्ययनगत समूह के छात्राओं की सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि	21
4.	अध्ययन क्षेत्र में कन्या शिक्षा की स्थिति एवं समस्याएं	32
5.	शिक्षकों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण	75
6.	निष्कर्ष एवं सुझाव	85
	Bibliography	*96*
	साक्षात्कार अनुसूची	*105*
	चित्र	*119*

नमूना SAMPLE

नमूना • SAMPLE

1

प्रस्तावना

Introduction

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 8 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजातियों की है। भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, मनिपुर, नागालैण्ड में बड़ी संख्या जनजातियों की है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहाँ जनजातियों की बहुलता है। जनजाति समुदाय समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन का केन्द्र रहा है। इसका कारण जनजातियों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान तो रहा ही है पर साथ ही इन क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, ऋणग्रस्ता, अशिक्षा, मद्यपान, विस्थापन, भूमिहस्तांतरण, कुपोषण तथा नक्सलवाद व उग्रवाद की समस्या का होना भी रहा है। इस समस्याओं के कारण आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में जनजातियों की स्थिति बेहतर नही हो पाया है। डॉ. एन. मजूमदार ने 1938 में अपने अध्ययन में भी जनजातियों की प्रमुख समस्याओं में उपरोक्त बातों को महत्वपूर्ण माना है।

आज देश के 200 से भी अधिक जिले वामपंथी विचारधारा पर आधारित आन्दोलनों के प्रभाव में है। नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित क्षेत्र को देश की मानचित्र पर देखें, तो यह स्पष्ट होता है, वामपंथी आन्दोलनों का प्रभाव मुख्य रूप से पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में है और ये क्षेत्र जनजाति बाहुल्य

SAMPLE

है। प्रस्तुत अध्ययन भी छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र दक्षिण बस्तर, राजनांदगांव जिले पर आधारित है।

यद्यपि नक्सलवाद को आज कानून और व्यवस्था की समस्या माना जा रहा है, लेकिन मूलतः यह एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति समस्या है, जिसका जन्म शोषण एवं सामाजिक विसंगतियों के परिणामस्वरूप ही हुआ है। इसे मिलने वाला जन समर्थन एवं इसके उन्मूलन में प्रशासनिक अमलों को मिलने वाली असफलता यह इंगित करती है, कि नक्सलवाद आंदोलन को भविष्य की बड़ी समस्या मानकर व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के प्रयत्न किये जावे, अन्यथा स्थिति भयावह होगी इसकी पूर्ण आशंका है।

नक्सली क्षेत्र के बच्चों के शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी होने का कारण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक परिवेश के साथ–साथ नक्सलवाद की समस्या भी है। नक्सलवादी नीतिगत तौर पर यह नहीं चाहते, कि क्षेत्र के जनजाति पढ़े लिखें, साक्षर हों, जागरूक हों, बाहरी दुनिया से जुड़े। यदि ऐसा होता है, तो वे अपने परिस्थितियों को समझने लगेंगे और अपनी खराब स्थिति का जिम्मेदार उनको मानकर उनका विरोध करेंगे। उनके दलम में भरती नहीं होंगे, उन्हें अपने नक्सली दलम में भरती करने के लिए युवक–युवती नहीं मिलेंगे, माँ–बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज देंगे, उनमें जागरूकता एवं सम्पन्नता आ जायेगी। अतः वे लोगों को निरक्षर बनाये रखना चाहते हैं। नक्सलियों के अस्तित्व के लिए यही आदर्श स्थिति है। अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे बच्चों को बचपन से ही नक्सली शिक्षा देने लगते हैं। उन्हें अपने दलम में भरती कर लेते हैं। नक्सलियों के द्वारा बच्चों के लिए एक पृथक केडर बाल संघम बनाया गया है, जो नक्सलियों के लिए सूचनाओं का संग्रहण करना तथा अन्य छोटे–मोटे कार्य करते हैं और सामान्य जन को उन पर संदेह भी नहीं होता है।

विभिन्न शोध अध्ययनों तथा समाचार पत्रों से ज्ञात तथ्यों से यह पता चलता है कि जनजातियों को निरक्षर रखने के लिए नक्सली शाला संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनके द्वारा शाला भवन, छात्रावास, आश्रम भवन आदि को ध्वस्त, तोड़ दिया जाता है, आश्रम शालाओं में बच्चों के लिए लाई गई खाद्य सामग्री को लूट लिया जाता है, शिक्षकों के साथ मारपीट, यहाँ तक हत्या भी कर दी जाती है। शिक्षक नक्सली भय से स्कूल जाने से डरते हैं।

इससे स्कूल बंद हो जाता है। नक्सली क्षेत्र में शिक्षक के रूप में कोई नौकरी करना नहीं चाहता है। शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली है। इससे जनजातियों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नक्सलियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में शाला भवनों को इसलिए तोड़ा जाता है, क्योंकि सुरक्षा बल नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान इन भवनों का उपयोग रात रूकने के लिए करते हैं।

ऐसे विषम परिस्थिति में नक्सलवाद इन जनजातियों के समक्ष आज एक गंभीर समस्या के रूप में आ खड़ा हुआ है, जो कि उनके जीवन–मरण का प्रश्न बन गया है। यद्यपि क्षेत्र के जनजातियों की यह समस्या एक नवीन समस्या है, लेकिन नया एवं केवल 42 साल पुरानी समस्या होने के बाद भी यह आज उनके सामने इतने विकराल रूप में खड़ा हो गया है, कि इसके चलते उनका पूरा जीवन धारा रूक गई है।

Statement of the Problem

प्रस्तुत शोध कार्य वामपंथी विचारधारा पर आधारित आन्दोलनों वाले क्षेत्रों में बालिकाओं की समस्याओं पर आधारित है। अध्ययन में वामपंथी आन्दोलन का जनजाति बालिकाओं के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का शोध परक अध्ययन किया गया है।

जनजातिय क्षेत्रों की अन्य सामाजिक आर्थिक पक्षों की भाँति अशिक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। 1931 की जनगणना के अनुसार केवल 0.7 प्रतिशत जनजाति ही शिक्षित थे। 1950 के पूर्व जनजातियों को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं थी, लेकिन 1947 में देश के स्वतंत्र होने तथा 1950 में संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा जनजातियों के शिक्षा के स्तर में वृद्धि कर राज्य तथा केन्द्र दोनों का उत्तरदायित्व हो गया। यही वजह है, कि जनजातियों की साक्षरता दर का प्रतिशत देश में औसत रूप से 29.60 प्रतिशत हो गया है, जो कि 2001 में 47.10 प्रतिशत तक पहुँच गया है, लेकिन इसके बाद भी दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों में शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

जनजाति समाज में गरीबी के कारण बच्चों के बचपन से ही आर्थिक अर्जन करके भरण–पोषण करने की शिक्षा देते हैं और उनका यह मानना है,

कि यदि बच्चे स्कूल जायेंगे, तो श्रम मूलक कार्य नहीं कर सकेंगे, इसलिए वे स्कूलों में अपने बच्चों का नाम तो लिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को नियमित स्कूल न भेजकर उनसे कृषि, जानवर चराने, छोटे बच्चों को पालने, खेतों की रखवाली करने आदि कार्य लिया जाता है। इसी के कारण जनजातियों में प्राथमिक शिक्षा भी पूरी न होकर अधूरी रह जाती है।

जनजातियों में शिक्षा के प्रति अरूचि का प्रमुख कारण सामाजिक है। उनके अन्दर व्याप्त इस पूर्वाग्रह के कारण कि उनके बच्चे पढ़–लिख कर उनसे अलग तथा दूर चले जायेंगे, तब उनकी देखभाल कौन करेगा, शिक्षा के अरूचि का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क शिक्षा पद्धति होने के बाद भी उन्हें इसकी सही–सही जानकारी नहीं है तथा उन्हें ऐसा लगता है, कि वे गरीब होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है।

वर्तमान में केन्द्र तथा राज्य शासन के द्वारा जनजातियों के शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनायें संचालित की जा रही है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना, प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, विद्यार्थी कल्याण योजना, आवासीय ब्रिज कोर्स, मॉडल स्कूल, छात्रावास, बालक एवं बालिका आश्रम विद्यालय, नेहरू पुरूस्कार, योजना तथा विभिन्न छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति जैसे कई योजनाऐं चलाई जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं।

शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सही क्रियान्वयन न हो पाने के कारण भी विद्यालय में छात्रों की नियमितता का अभाव पाया जाता है। दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों के रहने की स्थानीय व्यवस्था न होने, आवागमन के साधन न होने तथा नक्सली खतरों के कारण शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। नक्सलियों के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को तोड़ देने, आश्रम–छात्रावासों के राशन लूट लेने तथा शिक्षकों की हत्या कर देने से अध्ययन क्षेत्र के लगभग 178 ग्रामों में स्थानीय स्तर पर शाला संचालन नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र के बच्चों के लिए सड़क के किनारे आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे हैं, लेकिन इन आवासीय विद्यालय का लाभ उन्हीं बच्चों को मिल रहा है, जो वहाँ आ गये हैं। ऐसे बच्चों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत है। 50 प्रतिशत बच्चे अभी भी नहीं आये हैं, जिनके शिक्षा की

कोई व्यवस्था नक्सली समस्या के कारण नहीं हो पा रहा है। शिक्षक गांव में जाने को तैयार नहीं है। गांव में पाठशाला संचालित करने लायक कोई भवन नहीं है, अतः अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती एवं समस्या बनी हुई है। अध्ययन में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोध समस्या का शोध परक अध्ययन किया गया है।

Review of Literature

देश और विदेश के अनेक शोधार्थियों ने नक्सलवाद की समस्या, कारण और प्रभाव पर अध्ययन किए हैं पर विशेष रूप से नक्सलवाद और जनजाति बालिकाओं की समस्या पर शोध अध्ययन का अभाव है। तथापि अध्ययन विषय को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शोध अध्ययनों की समीक्षा निम्नानुसार है –

एल्विन (1951) के अनुसार "एक जनजातीय परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक रूप से आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इससे इनके जीवन–यापन के संघर्ष तथा परस्पारिक श्रम–विभाजन की योजना गड़बड़ा जाती है– बहुत से माँ–बाप ऐसी स्थिति में नही होते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके।

कट्टकयम, जेकब जान (1978) का अध्ययन विकासशील देशों में शिक्षा परिवर्तन की कुंजी के रूप से संबंधित रहा है। यह अध्ययन केरल राज्य के जनजातियों पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनजातीय संस्कृति और व्यवहार से पृथक ज्ञान का प्रसार करना रहा है, ज्यादातर जनजाति लाचार प्रशासनिक व्यवस्था और कमजोर नियोजन के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये।

एस. एन. रथ (1981) निम्न सुझाव देने के साथ–साथ समस्या का स्पष्ट विश्लेषण भी किया है :– पारम्परिक रूप से प्रशिक्षित एक जनजातीय बच्चा अपने वातावरण से अवगत होता है। वह अपना घर बनाना, खेती करना, कपड़ा बुनना आदि ऐसे सभी कार्यों से परिचित होता है जो उसे अपनी संस्कृति में ठीक–ठीक जीवन–यापन करने में सहायक होते है। औपचारिक शिक्षा का इस प्रकार जीवन से कोई तारतम्य नही है। अतः एक ऐसे पाठ्यक्रम तथा प्रणाली की संरचना होनी चाहिए जो जनजातीय परंपराओं, रीति–रिवाजों, स्थानीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना में एक

संतुलन स्थापित कर सके।

कार्तिकेश्वर, राऊत (2006) का अध्ययन जनजातियों में जीवन की गुणवत्ता पर शिक्षा के प्रभाव पर आधारित था, यह अध्ययन उड़ीसा के क्योंझर जिले के चार विकासखण्ड के संथाल, कोल्हा, भुयान, जोंगा, जनजाति पर आधारित था। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष में यह ज्ञात हुआ है कि जनजातियों में निरक्षरता जीवन के गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अध्ययनगत समूह के 65.5 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर पाये गये जबकि जनजातिय महिलाओं में निरक्षरता का प्रतिशत और भी अधिक था आधे से भी अधिक जनजाति परिवार परंपरागत तरीके से जीवकोपार्जन करते पाये गये।

दास, बी.सी. (2006) का अध्ययन – जनजातियों में प्राथमिक शिक्षा पर डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के प्रभाव पर आधारित था। अध्ययन उड़ीसा राज्य के जनजातिय बाहुल्य जिला रायगढ़ा गजपति और कालाहांडि के अठारह प्राथमिक विद्यालयों के 1000 स्कूली बच्चों, 36 सामुदायिक नेता, 80 अभिभावक, 34 शिक्षकों तथा कार्यक्रम के 57 शिक्षा क्रियान्वयन कर्ताओं के अध्ययन पर आधारित था। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम जनजातिय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने में पूर्णतः सफल रहा है। कार्यक्रम के फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों में अभूतपूर्व उपस्थिति (75–85) प्रतिशत पायी गई। कार्यक्रम के द्वारा न केवल जनजातिय अभिभावक बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हुये वरन् अध्ययनरत बच्चों में स्वअध्ययन, स्वच्छता, अनुशासन की प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखी गई है।

पुरबस कर, (2007) का अध्ययन – जनजातीय बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा और अकादमिक उपलब्धियों पर आधारित था। अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के 480 जनजातिय बच्चों जो कि संथाल, कोल्हा, भूमिज और भूयान जनजाति के थे। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि रचनात्मक क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच छात्र तथा छात्राओं दोनों में महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक था।

अशोक कुमार परिदा (2007) का अध्ययन – जनजातीय स्कूली छात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं और शैक्षणिक उपलब्धियों के मध्य संबंध पर आधारित था। यह अध्ययन उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले के

आश्रम विद्यालय, शासकीय विद्यालय और अनुदान प्राप्त विद्यालय के अध्ययन पर आधारित था। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि आश्रम विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएँ शासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की तुलना में भिन्न तथा श्रेष्ठ था। परिणामतः उनकी शैक्षणिक उपलब्धि भी श्रेष्ठ पायी गयी।

शर्मा, आलोक (2008) का अध्ययन हाई स्कूल स्तर के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति तथा अकादमिक प्रगति पर आधारित था। अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहरिक जिले के 17 विद्यालयों पर आधारित था। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अन्य वर्गो की तुलना में अधिक थी। इसी प्रकार उनका अकादमिक प्रगति भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से कम था।

सूमीत सरकार (2009) का अध्ययन मरते लोगों पर टिप्पणी से संबंधित है जिसमें उन्होंने मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लालगढ़ के आदिवासियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित और भेदभाव का शिकार है जैसे इतने बड़े क्षेत्र में केवल 01 डॉक्टर दो बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवाएं देता है। सरकार की यह टिप्पणी पूर्णतः भौगोलिक है।

जॉन हेरिस (2010) का अध्ययन भारत में नक्सल व माओवादी आन्दोलन पर आधारित है। अध्ययन में उन्होंने भारत में नक्सल आन्दोलन का इतिहास और इस विषय में देश के चुनिंदा शोधकर्ताओं तथा समाज कार्यकर्ताओं के योगदान की विस्तारपूर्वक चर्चा किया है। केनेडा के सिमन फ्रेजर विश्वविद्यालय का निर्देशक होने के साथ–साथ भारत के इस समस्या पर वे गहरी पैठ रखते हैं। उनका अध्ययन मुख्य रूप से उन बिन्दुओं की ओर इशारा करता है जहाँ माओवादी बड़ी संख्या में है और जन सामान्य में गहरी पहुँच रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जहाँ उनकी संख्या कम है फिर भी सुरक्षा बलों से संघर्ष कर रहे हैं। जिसे उन्होंने सैन्य संघर्ष की राजनीति की दुर्दशा के रूप में इंगित किया है। उनका मत है कि इसे अभिजनों और राज्य के द्वारा सर्मथन प्राप्त है, पर यह आन्दोलन निर्धन भूमिहीन कृषकों व आदिवासियों के खिलाफ है।

अल्पा शाह (2010) ने झारखण्ड क्षेत्र का उदाहरण देकर इस तथ्य को उजागर किया है कि सघन जंगली क्षेत्रों में नक्सली राज्य की भाँति कार्य करते हैं इन क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण करने वालों से, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बांध और पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदारों से पैसों की वसूली इनके मुख्य स्त्रोत हैं जिसके दम पर ये इन क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देते है।

मिक्लियन और अजय साहनी (2010) ने माओवादी तथा नक्सलवादी आन्दोलन को रोकने की दिशा में राज्य और पूंजी की भूमिका के विषय में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2005 तक की स्थिति में न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वरन सामान्य क्षेत्रों में भी जनसंख्या के अनुपात में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने में अन्य राज्यों झारखण्ड से पीछे है। अर्न्तराष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति होना चाहिए जबकि छत्तीसगढ़ में यह संख्या केवल 143 है ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एक चिंता जनक विषय माना जा सकता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में SPO की भर्ती 2006 में बडी संख्या में उस कमी को पूरा करने के लिए किया गया।

गौतम नवलखा (2010) ने माओवादी हृदय स्थल में दिन और रात शीर्षक अर्न्तगत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में लिखा है कि बस्तर क्षेत्र के क्रांतिकारी लोग समिति का वार्षिक बजट जिसे **जनतनम** सरकार के नाम से जाना जाता है को 3.6 लाख ठेकेदारों से टेक्स के रूप में, 5.0 लाख अन्य स्त्रोतों से तथा 2.5 लाख श्रम दान से जो कि स्थानीय परिवारों से एकत्रित होता है के माध्यम से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा तेंदूत्ता की रॉयल्टी के रूप में, बॉस और अन्य जंगली उल्पाद की रॉयल्टी के रूप में प्राप्त की जाती है। स्पष्ट है कि माओवादियों की आय का एक प्रमुख स्त्रोत स्थानीय ठेकेदारों व परिवारों से वसूला गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की ओर से 2013 में करवाये गये सर्वे जिसमें 05 जिलों को शामिल किया गया था के अनुसार राज्य में अब तक 01 लाख 78 हजार 500 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। रायपुर के आस पास औद्यौगिक इकाईयों, ट्रांसपोर्ट नगर के पास के बच्चे ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं जबकि मुंगेली, कांकेर, जांजगीर–चांपा और बलरामपुर में कृषि कार्यों में लगे होने के कारण प्रायमरी और मिडिल के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। सर्वे में जिन कारणों को प्रमुख माना गया है उनमें